

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील
प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 07/2020

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरु ।

अपीलांट

बनाम

1. हकीम खांन पुत्र इनायतखां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी वार्ड न0 28 अगुणा मोहल्ला चूरु तहसील व जिला चूरु ।
2. इनायत खां पुत्र रहमत खां कायमखानी निवासी वार्ड न0 28 अगुणा मोहल्ला चूरु तहसील व जिला चूरु ।
3. मोबीना बानो पुत्री भंवरुखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरु ।
4. रोशनी बानो पुत्री भंवरुखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरु ।
5. सुभानखां पुत्र भंवरुखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरु ।
6. सरवरबानो पुत्री भंवरुखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरु ।
7. हलीमा पत्नी भंवरुखां जाति कायमखानी निवासी बीनासर तहसील चूरु ।

रेस्पोंडेण्टस

- उपस्थित:—
1. तहसीलदार चूरु
 2. श्री सुरेन्द्र राहड़ अधिवक्ता रेस्पोंडेण्टस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरु जिला चूरु के
निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 के विरुद्ध अपील
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955

निर्णय

दिनांक:-26.03.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी चूरु जिला चूरु के निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 2534/805 तादादी 5.0586 हैक्टर रोही कस्बा चूरु में स्थित है । जिसका खाता विभाजन 10.07.2020 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया जिसमें कानूनी त्रुटि रह जाने से उक्त त्रुटि व दोष को दूर करने के लिये यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट ने अपने अपील मीमो में कथन किया है कि कृषि भूमि ख0न0 805 जिसके नये नम्बर ख0न0 2534/805 व 2535/805 अविभाजित है इन खसरो नम्बरों में कोई बंटवारा नहीं हुआ है जिसमें पत्थर गढी मौके पर विभाजन तारबंदी बाड़ किये जाने के आदेश वादी/रेस्पों द्वारा डिक्री चाही गयी थी जिस हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2020 सीमाकन करवाये जाने बाबत पेश किये गये थे । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार के विरुद्ध वाद कारण उत्पन्न किये बिना ही व कानून के अहम बिन्दू को दरकिनार करते हुए दावा का निस्तारण कर प्रारम्भिक व अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी और नायब तहसीलदार चूरु द्वारा अपने हस्ताक्षर करके प्रारम्भिक विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जिसमें कानून त्रुटि रह जाने से उक्त त्रुटि व दोष को दूर करने तथा पत्रावली में आगामी आदेश पारित करने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी दिनांक 15.10.2020 को प्रस्तुत किया लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना निर्णय किये असल प्रार्थना पत्र वापस लौटा दिया अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी का निर्णय किया जाना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा न किया जाकर सीधा ही निर्णय पारित कर कानूनन भूल की है । अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 को अपास्त करवाने का श्रम करावे ।
3. रेस्पोंडेन्टस अभिभाषक न अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत कृषि भूमि ख0न0 805 जिसके नये नम्बर ख0न0 2534/805 तादादी 5.0586 हैक्टर रोही कस्बा चूरु में रेस्पों/वादी एवं अपीलांट/प्रतिवादी सं0 4, 5 ता 9 के खातेदारी हिस्सों की कृषि भूमि का खाता विभाजन मौके के कब्जा अनुसार अपीलांट/प्रतिवादी रेस्पों/वादी के द्वारा आपसी सहमति से खाता विभाजन हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया मौका व कब्जा काश्त के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया जो कि नायब तहसीलदार द्वारा तैयार कर भिजवाया गया जो सभी पक्षकारों की आपसी सहमति अनुसार किया गया था । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी आधार पर अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 पारित की गयी है । इस विभाजन प्रस्ताव से किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं रही इसके उपरांत भी तहसीलदार चूरु द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की है जो निराधार है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने उभय पक्ष की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 5 परिसीमा अधिनियम मय शपथ पत्र पर बहस सुनी व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुऐ अपील अन्दर मियाद स्वीकार की गयी । वादगत कृषि भूमि ख0न0 2534 / 805 तादादी 5.0586 हैक्टयर राही कस्बा चूरु कर खाता विभाजन सभी पक्षकारों की आपसी सहमति से किया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर तैयार कर भिजवाया गया जिस पर किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति नही रही है और इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 पारित की गयी है जिसमें इस न्यायालय को किसी प्रकार की त्रुटि नजर नही आती है और ना ही अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील व पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य व सबुत प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि इस निर्णय से राजकीय हानि हुई हो । अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का निर्णय करने से पूर्व अतिम निर्णय व डिक्री जारी करने की बात कही है । प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के अवलोकन से यह पता चलता है कि यह प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय में 15.10.2020 को प्रस्तुत किया गया था जबकि अतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 को ही पारित की जा चुकी थी ऐसी स्थिति में धारा 151 सीपीसी का बाद निर्णय पेश किया जाना निराधार है ।
5. अतः उक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2020 की पुष्टि की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दप्तर हो अधिनस्थ न्यायालय की मुल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिनांक 26.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर